'बेसिक' में 'फूटा' बाबूओं के फर्जी 'नियुतियों' का 'बम'

वर्तमान बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर में कोई डायट, तो कोई एमडीएम का डीसी, कोई लेखाकार तो कोई वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत

चयन समिति ने जिसका चयन किया, उसे न करके भारी रकम लेकर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों का कर दिया, ऐसे 14 बाबू हैं, जिनकी नियुक्ति की जांच करने की मांग उठी

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...अभी तक आप लोगों ने अब तक बेसिक विभाग में फर्जी 'गुरुजी' के बारे बहुत सुना और पढ़ा होगा, मगर आज हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 कथित फर्जी बाबूओं की नियुक्ति के बारे में बताने जा रहें है। एक तरह से बेसिक विभाग में बाबूओं के फर्जीवाड़ा का बम फूटा है। यह बम किसी और ने नहीं बल्कि बस्ती/संतकबीरनगर के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेंद्रनाथ तिवारी ने फोड़ा।

इन्होंने कथित फर्जी बाबूओं की सूची देते हुए सीएम से शिकायत करते हुए इसकी जांच एसआईटी से करानें की मांग की है, इस फर्जीवाड़े में लिप्त तत्कालीन बीएसए और पटल सहायकों की भी जांच कराने को लिखा है। इतना शातिर दिमाग सिर्फ बेसिक विभाग के बाबूओं के पास ही देखने को मिल सकता है। चयन समिति ने जिन बाबूओं का चयन किया, उसे न करके दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले का कर दिया, यानि जो हक पहले स्थान वाले को मिलना चाहिए था, उसे तत्कालीन पटल सहायकों ने उन लोगों का हक छीन कर ऐसे व्यक्ति को दे दिया, जिसका चयन ही नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, कि इतने बड़े फर्जीवाड़ें को अंजाम देने में अकेला बाबू नहीं हो सकता, अवष्य इस फर्जीवाड़े में तत्कालीन बीएसए का हाथ अवश्य रहा होगा। इसी का पता एसआईटी को लगाना है। अब तो यह जांच का विषय हैं, कि इस फर्जीवाड़े में किस-किसकी भूमिका रही। जिन बाबूओं का फर्जी तरीके से चयन होने की षिकायतें की गई, वर्तमान में उनमें कोई मंडलीय एमडीएम समन्यवक तो कोई एमडीएम का डीसी है। कोई डायट में तैनात हैं, तो कोई बीएसए कार्यालय में। बस्ती के लेखाकार भी इसकी चपेट में है। सबसे अधिक तैनाती सतंकबीरनगर के बीएसए कार्यालय में वर्तमान में है। इसका खुलासा आरटीआई के तहत मिली जानकारी से हुआ।

बीएसए कार्यालय, बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर में 'हरि से बड़ा हरि का दासा' एकदम चरित्रार्थ हो रहा है, अर्थ का अनर्थ करना अगर किसी को सीखना हो तो वह बीएसए के बाबूओं से सीख सकता है। बीएसए और उनके अधीन बाबूओं के द्वारा इतने भ्रष्टाचार और कदाचार किए गएं हैं, जिसके बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बीएसए कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार के जीरो टालरेंस नीति को लेकर बस्ती/संतकबीरनगर के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि अनेक स्थानों पर मान्यता प्राप्त अषासकीय जूनियर हाईस्कूल में बीएसए ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, और यह इतने चालाक हैं, कि आरटीआई का उत्तर देते समय संलग्न हैं, लिखना नहीं भूलते, ताकि लगे कि पूरी सूचना दी गई, मगर, चालाकी यह करते हैं, कि जिस स्थान पर संलग्न लिखा होता है, और जिसे स्टेपल किया जाता है, उस टुकड़े को फाड़कर निकाल देते है। ताकि यह कहने लायक रहे कि देखिए हमने को संलग्न भी किया और स्टेपल भी किया।

आरटीआई में हुआ खुलासा, वर्तमान में सबसे अधिक संतकबीरनगर में तैनात

बस्ती/संतकबीरनगर के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेंद्रनाथ तिवारी ने सीएम से इसकी जांच जांच एसआईटी से कराने की मांग की, इस फर्जीवाड़े में लिप्त तत्कालीन बीएसए और पटल सहायकों की भी जांच कराने को लिखा

कहते हैं, कि समय-समय पर बीएसए बनाई गई चयन समितियों के निर्णय की आख्या अपने-अपने हिसाब से करते रहें है। जिन लोगों की नियुक्ति को फर्जी होने की शिकायत की गई, उनके पास आय से कई गुना संपत्ति हैं। बाबू अपने साहबों को अंधेरें में रखकर उल्टा सीधा काम कराते रहते है। उदाहरण स्वरुप सरदार पटेल अवर माध्यमिक विधालय काली जगदीषपुर संतकबीरनगर में चयन समिति ने जिन तीन नामों को क्रमवार भेजा, उसे पटल सहायक ने क्रमवार को तोड़कर जिसका दूसरे और तीसरे स्थान पर उसे पहले स्थान पर करके नियुक्ति पत्र थमा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण बीएसए कार्यालय में देखने को मिल जाएगें। अब जरा बाबूओं और बीएसए के बीच का खेल देखिए। बाबू कहते हैं, हमने रिकार्ड संलग्न कर दिया, और रिकार्ड पर हस्ताक्षर करने वाले बीएसए साहब कहते हैं, कि उन्हें मालूम ही नहीं, बीएसए खुद शिकायतकर्ता से रिकार्ड मांग रहे हैं।

'एसआईटी' के 'दायरे' में यह 'बाबू'

जिस नियुक्ति को फर्जी बताते हुए एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई, उनमें धमेंद्र कुमार वरिष्ठ सहायक पूर्व में सिद्धार्थनगर वर्तमान अमेठी, अनिल कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक पूर्व सिद्धार्थनगर वर्तमान डीआईओएस बस्ती, राकेष मणि लिपिक पूर्व सिद्धार्थनगर वर्तमान बस्ती, मुकुल मिश्र लिपिक सिद्धार्थनगर, विजय कुमार लिपिक पूर्व संतकबीरनगर वर्तमान बस्ती, विजय कुमार स्टेनो संतकबीरनगर, सुनील मिश्र लिपिक संतकबीरनगर, देव कुमार उपाध्याय लिपिक संतकबीरनगर, धीरेंद्र प्रताप चंद्र एमडीएम डीसी संतकबीरनगर, मिथिलेष कुमार एमडीएम समन्यवक बस्ती मंडल, षैलेंद्र कुमार गौतम वरिष्ठ सहायक एडी बेसिक बस्ती कार्यालय वर्तमान डायट बस्ती एवं संजय कुमार श्रीवास्तव लेखाकार पूर्व स्तंकबीरनगर वर्तमान में इनकी तैनाती बस्ती में है।

छोटे 'बच्चों' का 'अनाज-वजीफा' हड़पने के बाद अब बड़े 'बच्चों' पर गड़ाई 'नजर'

पहले बेसिक ने सरकारी जमीन पर जू.हा. स्कूल की मान्यता देकर पहुंचाया नुकसान

अब माध्यमिक को भी चूना लगाने की फिराक में, ग्रांट लेना चाहते

ग्रांट की मंजूरी देने से पहले पहुंची माध्यमिक की टीम को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा

कागजों में संचालित हो रहे कुदरहा ब्लॉक के राम पारषद इंटर कालेज अमरौना का सच

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...सालों तक कागजों में सरकारी जमीन पर बिना बच्चों और षिक्षकों के एमडीएम और वजीफा का हक मारकर विधालय चलाकर सरकार की आंख में धूल झोंकने वाले राम पार्षद शास्त्री इंटर के प्रबंधतंत्र का पेट नहीं भरा तो माध्यमिक के ग्रांट को हड़पने की साजिश कर डाली। माध्यमिक तक ग्रांट हासिल करने के लिए आवेदन कर डाला, जब कि प्रबंधक को अच्छी तरह मालूम हैं, कि उसके विधालय का विवाद चल रहा हैं, और बीएसए चाहें तो कभी जूनियर हाई स्कूल की मान्यता को निरस्त कर सकते है। फिर भी प्रबंधक की हिम्मत तो देखिए माध्यमिक तक ग्रांट पाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जबकि विधालय में न तो बच्चों को नामांकन हैं, और न कोई शिक्षक।

माध्यमिक तक का ग्रांट पाने के लिए डीआईओएस स्तर से विधालय की जांच पड़ताल किया जाता है, देखा जाता है, कि कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षकों की तैनाती हैं, विधालय में कितने कमरे और किस साइज के हैं। इसकी जांच करने के लिए जब डीआईओएस की टीम विकास श्रीवास्तव की अगुवाई में विधालय पहुंची तो वहां पर टीम को गांव वालों का काफी विरोध झेलना पड़ा। इतना विरोध होगा इसका अंदाजा टीम को नहीं था। टीम को न तो कोई बच्चा मिला और न कोई शिक्षक, केवल बाबू और अनुचर मिले। कालेज का नाम नोप जोख होते देख बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए, इन लोगों का कहना था, कि कालेज ग्राम समाज की भूमि पर बना है। जिसका लाभ प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत हित में लिया जा रहा है। यहां तो केवल गैर मान्यता वाले विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को टीसी मार्कसीट देने का खेल किया जाता है। इसके एवज में उनका वजीफा और राशन डकार लिया जाता है।

इस बात का गवाह कालेज की प्रवेश पंजिका है। बच्चों का पता देखा जाए तो मामला स्पष्ट हो जाएगा, रजिस्टर में दस किलोमीटर दूर कुदरहा, परेवा, मटियरिया, उजियानपुर व मसोड़वा आदि के बच्चों का नाम दर्ज मिलेगा। यह हाल तब का है जब अभी जूनियर का ही ग्रांट मिला है, माध्यमिक का भी ग्रांट लेकर इसे अपनी कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यहां 2015 से माध्यमिक स्तर की पढ़ाई नहीं हो रही है। केवल गैर मान्यता विद्यालय के बच्चों का नाम दर्ज कर कालेज की मान्यता बचाने व ग्रांट पाने की कोशिश हो रही है। गांव वालों ने यह भी बताया कि नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। डीआईओएस जगदीश शुक्ल ने बताया कि जो सही है, उसी की रिपोर्ट जाएगी।

पहले 'दिल' तो 'मिलाइए', फिर स्वागत 'करवाने' का ढोंग 'रचिए'!

किसानों ने सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछा, जब रोजगार चला गया, और भुगतान नहीं हुआ तो अब क्यों आएं

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...वाल्टरगंज चीनी मिल के किसानों का पिछले छह साल से 40 करोड़ बकाया हैं, भुगतान न होने से जाने कितने किसानों के बेटियों की शादी नहीं हो पाई, इलाज के अभाव में और बीमार होते गएं, हडिडयां तक दिखने लगी। किसान तबाह हो गया, तब किसी नेता ने किसानों के घरों में जाकर यह तक देखने का प्रयास नहीं किया, कि किसानों के परिवारों पर क्या बीत रही है? चीनी मिल बंद हो गया, लेकिन नेताओं ने इसे चलाने के लिए उतना मेहनत नहीं किया, जितना वह चुनाव के समय वोट मांगने में कर रहें है।

अगर सांसदजी किसानों के लिए कुछ किए होते तो आज किसान खुश होता और स्वांय स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ता, तब सांसदजी को मैनेज वाला स्वागत न करवाना पड़ता। किसानों का गुस्सा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष पर उस समय फूटा जब यह दोनों 50 लाख के भुगतान कराने का श्रेय लेने गए थे। किसानों ने दोनों नेताओं से पूछा कि आज क्यों आए हैं, उस समय क्यों नहीं आए जब हमारा परिवार भुगतान न होने से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका था। कहा कि कोई नेता यह देखने नहीं आया कि उनके घरों में दिपावली के दिन दिए जल रहे हैं, कि नहीं, होली मनाई जा रही है, कि नहीं? बहरहाल, जिसका डर था, वही हुआ, भले ही दोनों नेता फूलों से लदे हुए फोटों में दिख रहें हैं, लेकिन यह माला किसानों ने नहीं पहनाया और न स्वागत ही किया, बल्कि मैनेज था। सवाल उठ रहा है, कि जब स्वागत करने वालों में एक भी किसान नहीं, तो फिर स्वागत किन लोगों ने किया? दोनों नेताओं को एक साथ देख लोग कहने लगे कि दिल तो मिला नहीं तो फिर स्वागत करवाने का ढ़ोग क्यों रच रहें? स्वागत होते समय नेताओं के चेहरें पर जो खुषी होनी चाहिए, वह दिखा ही नहीं, न सांसदजी मुस्करा रहें और न जिला पंचायत अध्यक्ष ही।

जिले की वाल्टरगंज चीनी मिल पर वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2017-2018 तक के गन्ना बकाया मूल्य हैं, सीजनल श्रमिको के बकाया वेतन पर किसी नेता का पाषाण हृदय नही पसीजा उक्त मिल पर बकाया के लिए निरंतर मिल श्रमिक ही लड़ते आ रहे है, जिसका प्रतिफल रहा कि दो करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान दो किश्तों में व नियमित श्रमिको का वेतन भुगतान हुआ, तब कोई नेता श्रेय लेने नहीं किसानों के बीच पहुंचा। 2018 में एक नेताजी फर्जी मिल मालिक खरीददार आने पर माला जरुर पहने, नेताजी को कहां पता था कि वह नटवर लाल है। यदि मिल चल गई होती तो नेताजी के खाते में एक उपलब्धि जरुर जुड़ जाती, 2018 से 2023 तक चीनी मिल के श्रमिकों के घर होली दिवाली नहीं मना रोजगार भी चला गया आर्थिक तंगी से जूझ रहे चीनी मिल श्रमिको के बच्चे पठन पाठन से वंचित रह जा रहे हैं तब किसी नेता को ख्याल नहीं आया, चीनी मिल प्रबंधतंत्र ने अभी दो चार दिन पहले 50 लाख का चेक सौंपा तो नेताओं द्वारा श्रेय लूटने की होड़ लग गई, जबकि बताते चलें चीनी मिल पर समस्त बकाया न देने पर आरसी जारी है, और यह जो पैसा आ रहा है, वह आरसी के तहत ही आ रहा है, इनमें किसी भी नेता और अधिकारी की कोई भूमिका नहीं।

यह भी जान लीजिए वाल्टरगंज चीनी मिल चलती दशा में बिना किसी नोटिस के बंद कर दी गई, आन पेपर मिल नहीं बंद है, न ही कहीं से मिल बंद करने का आदेश प्राप्त है। एक मिल चलवाने का श्रेय तमाम नेता ले रहे हैं। वाल्टरगंज चीनी मिल बंद करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। किसान कह रहे हैं, कि जनता, श्रमिक एवं किसान तब मानते, जब नेता मिल बंद होने से बचा लेते, बकाया दिलवा देते, चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद अधिनियम का सीधे सीधे उल्लंघन किया जा रहा है, नियमानुसार एक्ट के मुताबिक 14 दिन में विक्रय गन्ना मूल्य के भुगतान की व्यवस्था है इसका पालन नहीं कराते टैगिंग आदेशों का पालन नहीं कराते केवल छल द्वेश पाखण्ड का पाठ पढ़ते पढ़ाते हैं नेता।

किसानों और सीजनल कर्मियों के घरों में वेतन न मिलने से सालों से होली और दिपावली के दीप नहीं जल रहे, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई

जब किसानों का दो करोड़ का भुगतान हुआ तब कोई नेता श्रेय लेने नहीं आया, 50 लाख का श्रेय लेने और सैकड़ों रुपये का माला पहनने के लिए चले आए

'घोटालेबाजों' ने 'क्षेत्र पंचायत निधि' पर किया 'हमला'

विक्रमजोत के केशवपुर में रानीपुर कठवनिया स्कूल पिच रोड से लालपुर गांव की शरहद पांच लाख की लागत से 190 मी सीसी रोड का हो रहा घटिया निर्माण

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...क्षेत्र के लोग चिल्लाते रह जाते हैं, शिकायतें करते-करते थक जा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ब्लॉक खामोश, ब्लॉक प्रमुख चुप और मुख्यालय के लोगों का कहना ही क्या, इन्हें तो नेताओं की जीहजूरी करने से फुर्सत मिले तब यह शिकायतों पर ध्यान दें। इसी तरह का एक मामला विक्रमजोत विकास खंड के केशवपुर मे क्षेत्र पंचायत मद से बन रही सीसी रोड के घटिया निर्माण का सामने आया। यहां के ग्रामीणों ने घटिया निर्माण होने का आरोप लगाया।

केशवपुर के विनय कुमार मिश्रा ने सीएम और डीएम से षिकायत करते हुए कहा कि रोड निर्माण में पीले ईंट का प्रयोग कर मानकविहीन कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण स्थल पर सीआईबी बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे गांव वालों को पता ही नहीं चल पाता कि सड़क किस निधि से बन रही है, कौन बनवा रहा है, कि इसकी लागत कितनी है। वैसे भी पूरे जिले में क्षेत्र पंचायत निधि का अधिकांश कार्य कागजों में होता है, चूंकि इस निधि की जांच नहीं होती, इस लिए प्रमुख से लेकर ठेकेदार और बीडीओ तक मौज करते है। इस निधि की बोली लगाई जाती है, 50 फीसद तक बखरा इसमें चलता है। शिकायत में बेहद घटिया ईट (पीला) और गैर मानक अनुपात मे सीमेंट बालू का प्रयोग हाने की बात कही गई है। स्थानीय ग्रामीणों के आपत्ति करने के बावजूद अधिकारी उसे अनसुना कर देतें है।

शुक्रवार को सीसी रोड पर प्रयोग में लायी जा रही घटिया ईट की तस्वीर वायरल होने पर लोग विभागीय भष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। शिकायत कर्ता ने डीएम से जाँच करवाने की मांग किया की है। इस संबंध में निर्माण कार्य की तकनीकी सहायक विजय कुमार मालवीय ने बताया कि केशवपुर गांव में रानीपुर कठवनिया प्राथमिक विद्यालय पिच रोड से लालपुर गांव की शरहद तक क्षेत्र पंचायत मद से लगभग पांच लाख की लागत से 190 मी सीसी रोड का निर्माण चल रहा है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल ने बताया शिकायत मिली है। दो सदस्य टीम गठित कर भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महापंचायत में गरजे किसान, वीसी को सौंपा मांगपत्र

तेजयुग न्यूज

हापुड़ : आनंद विहार योजना के लिए भवन, दुकानों व कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में शुक्रवार को किसानों व भवन बचाओ संघर्ष समिति की एचपीडीए कार्यालय के बाहर महापंचायत हुई। जिसमें भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। किसानों की नारेबाजी और तालाबंदी की सूचना पर मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान किसानों ने अपना मांग पत्र सौंपा तथा उपाध्यक्ष में लिखित आश्वासन की मांग की।

शुक्रवार को प्राधिकरण कार्यालय के बाहर महापंचायत का आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों व व्यापारियों ने भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष पवन हूण ने कहा कि अगर चार बजे तक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसानों की समस्या सुनने के लिए धरना स्थल पर आते हैं तो ठीक है, अन्यथा कार्यालय पर ताला लगाकर कब्जा कर लिया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही।

शाम करीब चार बजे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन गौड़ धरना स्थल पर पहुंचे और समस्या सुनी। इस दौरान किसानों ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि दिल्ली रोड पर चमरी से बालाजी मंदिर तक किसानों एवं प्राधिकरण के बीच विवादित भूमि की सड़क से 100 मीटर की पट्टी छोड़ी जाए। करार के अनुसार छह प्रतिशत विकसित भूखंड मिले, किसानों व भू-स्वामियों पर लगाए गए अन्य प्रकार के शुल्क समाप्त कराए जाएं, पूर्व के बने भवनों पर लगाए गए 19000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के शुल्क को समाप्त किया जाए, पीड़ित किसानों की 100 मीटर के बाद नए अधिग्रहण कानून के तहत जमीन का मुआवजा दिया जाए अन्यथा 70 प्रतिशत भूमि किसान को और 30 प्रतिशत भूमि प्राधिकरण को दी जाए। दूसरे जिलों में प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाया जाए। किसान नेता संजय त्यागी ने कहा कि प्राधिकरण की जो भी बोर्ड बैठक हो, उसमें किसानों और भवन बचाए संघर्ष समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हों। जो भी निर्णय लिया जाए, उनकी उपस्थिति में हो।

'नीलम सिंह' ने 'विकलांग' परिवार पर लुटाया 'प्यार'

दरियादिली दिखाते हुए अपने कोष से इलाज कराने को विकलांग परिवार सहित अन्य तीन पीड़ितों को दिया 15 हजार

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...अगर किसी ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष से यह पूछा जाए कि क्या आप ने अपने क्षेत्र के गरीबों और असहाय लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए अध्यक्ष विवेकाधीन कोष की स्थापना की है, तो नगर पंचायत नगर की चेयरपर्सन नीलम सिंह को छोड़कर अन्य सभी बगले झांकने लगेंगे।

हर साल करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले अगर अपने मानदेय का 15 हजार रुपया जनता के कल्याण के लिए सुरक्षित कर लेगें तो उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर उन गरीबों पर फर्क अवष्य पड़ेगा, जिन्हें अगर एक हजार भी इलाज के लिए मिल जाए, तो उसके लिए डूबने को तिनके का सहारा जैसा होगा। यहां पर बात पैसे की भी नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है, आपकी उस सोच कि जिसमें आप ने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कैसी सोच रखी है? जरा उस परिवार से पूछिए जिसके चार बच्चें विकलांग हों, और जिसका पति बीमार हो, अगर ऐसे में उसे कुछ हजार की आर्थिक मदद मिल जाती है, तो वह परिवार नीलम सिंह को भगवान जैसा मानेगा।

अगर, इसी लिए अन्य अध्यक्षों से भी इसी तरह का कोष स्थापित करने की मांग उठ रही है। ताकि उनके क्षेत्र में हर माह कई गरीब परिवार को इलाज सहित अन्य आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा मिल सके। लूटपाट करने वाले अध्यक्षों को अपनी सोच बदलनी होगी, और समाज के उन वर्गों के लिए कुछ करना होगा, जिन्हें आवश्यकता है। इस तरह का कोष स्थापित कर नीलम सिंह देश/प्रदेश की पहली चेयरपर्सन बन गई है।

नगर पंचायत नगर की चेयरपर्सन नीलम सिंह राना ने क्षेत्र के तीन पीड़ितों को नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया। उन्होंने बताया कि सहायता पाने वाली टेमा निवासिनी गुड़िया पाण्डेय के चार बच्चे विकलांग है और फालिज के शिकार पति की दवा चल रही है। इसी प्रकार धुसुरिया निवासी दुर्गा प्रसाद मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर उपचार करा रहे हैं तथा नगर बाजार निवासी राजन सोनी की दूकान में आगजनी के कारण सारा सामान जलकर राख हो गया था। इन तीनों परिवारों को पांच-पांच हजार रुपये का चेक दिया गया। चेक पाने वाले परिवार के लोगों ने चेयरपर्सन और उनके परिवार को फलने-फूलने का आर्शीवाद दिल से दिया। इसे ही कहते हैं, असल में जनता की सेवा। कहा कि दैवी आपदा और दुर्घटना के शिकार नागरिकों की सहायता के लिए नगर पंचायत सदैव तत्पर रहेगा।

ऐसे लोगों की आर्थिक मदद के लिए सरकारी तंत्र से भी सहयोग का प्रयास किया जाएगा। भाजपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख राना दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि नगर बाजार देश की इकलौती ऐसी नगर पंचायत है जहां पीड़ितों के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकाधीन कोष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस अवसर पर सभासद राजेश पाण्डेय, विजय जायसवाल, राज कुमार चैधरी,राम सजन यादव, नियाज अहमद, संजय सोनकर, बिंदूलाल, तुलसीराम, अखिलेश यादव, विजय सहनी, दिनेश चैरसिया, वीरेंद्र कुमार, यशराज केके, संदीप कुमार, सत्यराम निषाद, देवेश धर द्विवेदी, राकेश पाण्डेय, भाजपा नेता डा अनिल श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे।

नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकाधीन कोष का लाभ पाने गुड़िया पांडे के चार बच्चे विकलांग, पति बीमार

अगर इस तरह के किसी परिवार को सरकारी नहीं बल्कि बनाए गए कोष से इलाज के लिए धन मिलता है, तो यह उस परिवार के लिए डूबते का तिनका सहारा जैसा होता